

दिनांक: 14.03.2024

समय : 09:00 ए.एम.

प्रादेशिक समाचार
आकाशवाणी जयपुर-अजमेर

- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पेटीएम फास्टैग का उपयोग करने वालों को कल से पहले किसी अन्य बैंक के फास्टैग की सुविधा प्राप्त करने की सलाह दी।
- जल संसाधन विभाग ने 46 अभियंताओं और कार्मिकों के स्थानांतरण ईआरसीपी कार्यालय में किये-संशोधित परियोजना के काम में आएगी तेजी।
- राज्य में विशेष योग्यजन निदेशालय के तहत विशेष विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए स्कूल एट हॉम शैक्षणिक हेल्पलाईन की शुरुआत।
- विश्व किडनी दिवस आज-इस साल का विषय – सभी के लिए किडनी स्वास्थ्य।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण-एनएचएआई ने पेटीएम फास्टैग उपयोग करने वालों को सलाह दी है कि कल यानि 15 मार्च से पहले किसी अन्य बैंक के फास्टैग की सुविधा प्राप्त करें। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि इससे फास्टैग उपयोग करने वालों को जुर्माने से बचने और राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा करते समय दुगुने शुल्क के भुगतान से बचने में मदद मिलेगी। पेटीएम पेमेंट बैंक पर प्रतिबंधों के संबंध में रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार 15 मार्च के बाद पेटीएम फास्टैग को रिचार्ज या टॉप-अप नहीं किया जा सकेगा, लेकिन इस तारीख के बाद भी पेटीएम फास्टैग में बची राशि का उपयोग किया जा सकेगा। एनएचएआई ने पेटीएम फास्टैग उपयोग करने वाले सभी लोगों से देशभर के राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुगम और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने के उपाय करने का आग्रह किया है।

भारी उद्योग मंत्रालय ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोत्साहन योजना 2024 की घोषणा की है। इस योजना के तहत चार महीने में पांच सौ करोड़ रुपये के कुल परिव्यय किए जाएंगे। यह प्रक्रिया अप्रैल से जुलाई महीने तक चलेगी। मंत्रालय ने बताया कि इस योजना में पंजीकृत ई-रिक्शा, ई-कार्टस और एल-5 मोटर वाहन सहित सिर्फ इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहन और इलेक्ट्रिक तीन पहिया वाहन स्वीकृत होंगे। इस योजना से देश में ईवी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास और ग्रीन मोबिलिटी को गति मिलेगी।

जल संसाधन विभाग ने 46 अभियंताओं और कार्मिकों के स्थानांतरण ईआरसीपी कार्यालय में किये हैं। इनमें 27 अभियंता, अभियांत्रिक वर्ग के 7 अराजपत्रित और मंत्रालयिक वर्ग के 12 अराजपत्रित कार्मिक शामिल हैं। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बताया कि पूर्वी राजस्थान में पेयजल, सिंचाई और औद्योगिक विकास के लिए संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है। इसके मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए विभाग पर्याप्त संख्या में श्रमिक नियुक्त कर रहा है।

राज्य सरकार ने कल भारतीय पुलिस सेवा के सात अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इनमें पांच जिलों के पुलिस अधीक्षक बदले गये हैं। कार्मिक विभाग के आदेश के अनुसार अभिजीत सिंह को सीआईडी सीबी में लगाया है। श्याम सिंह को जयपुर में पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय), लक्ष्मणदास को प्रतापगढ़, बृजेश ज्योति उपाध्याय को करौली और सुमित मेहरड़ा को धौलपुर, मोनिका सेन को डूंगरपुर और कुंदन कंवरिया को बालोतरा पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है।

आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार की संशोधित वेबसाइट शुरू की गयी है। केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल नई दिल्ली में इनकी शुरुआत की है। उन्होंने संशोधित न्यूज ऑन

एआईआर एप भी जारी किया। श्री ठाकुर ने प्रसार भारती प्रसारण के लिए साझा ऑडियो विजुअल-शब्द भी रिलीज़ किया।

इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि लोक प्रसारक के रूप में दूरदर्शन और आकाशवाणी वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने नेटवर्क के माध्यम से दोनों लोक प्रसारकों ने देश के हर कोने में स्थानीय भाषा को प्रोत्साहन देकर सभी लोगों तक जानकारी पहुंचाई है।

राज्य में विशेष योग्यजन निदेशालय के अधीन आने वाले विशेष विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए स्कूल एट हॉम (24x7 शैक्षणिक हेल्पलाईन) लॉन्च की गयी है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कल जयपुर में इसकी शुरुआत की। उन्होंने बताया कि स्कूल एट होम कार्यक्रम एक समावेशी शैक्षिक पहल है, जो स्कूली शिक्षा को सीधे दिव्यांग बच्चों और वंचित विद्यार्थियों के घरों तक बिना इन्टरनेट और बिना स्मार्ट फोन के पहुंचाता है। यह 1 से 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के साथ सह-पाठ्यक्रम, शैक्षिक कार्यक्रमों और ऑनलाईन कक्षाओं के साथ उपलब्ध है। श्री गहलोत ने कल अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के बेहतर संचालन, सुधार और सुझाव के लिए प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की। राज्य सरकार के नीतिगत दस्तावेज संकल्प पत्र 100 दिवस कार्य योजना की अनुपालना में इस बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रतिनिधियों ने योजनाओं के बेहतर संचालन के लिए सुझाव दिये। मंत्री ने बैठक में कहा कि राज्य सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है।

सरिस्का बाघ अभ्यारण्य में बाघिन एसटी 12 ने एक बार फिर 3 शावकों को जन्म दिया है। इससे वन्यजीव प्रेमियों में खुशी की लहर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रकृति की अद्वितीय विरासत बाघों का होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि शक्ति, खूबसूरती और सामर्थ्य के प्रतीक, 'राष्ट्रीय पशु' बाघ के संरक्षण-संवर्धन के लिए सरकार संकल्पबद्ध है।

हनुमानगढ़ के रावतसर में धन्नासर के पास आज एक ट्रक और जीप की टक्कर में तीन महिलाओं सहित चार लोगों की मौत पर ही मौत हो गई। दो घायलों को रावतसर ट्रामा सेंटर पहुंचाया गया। एक गंभीर घायल को जिला चिकित्सालय रैफर किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधर, सिरोंही जिले के आबूरोड में कल मिट्टी ढह जाने से चार मजदूर दब गए। इनमें से दो मजदूरों की मौत हो गयी। दो अन्य मजदूरों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

आज विश्व किडनी दिवस है। किडनी के स्वास्थ्य और सामान्य कार्य को प्रभावित करने वाली विभिन्न बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को यह दिन मनाया जाता है। इस साल किडनी दिवस का विषय है – सभी के लिए किडनी स्वास्थ्य। यह गंभीर किडनी रोग के बढ़ते खतरों और विभिन्न स्तरों पर चुनौतियों से निपटने के लिए किडनी की समुचित देखभाल करने पर केंद्रित है। किडनी शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में शामिल है और यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालकर उसे स्वस्थ रखने में सहायता करती है। एम्स नई दिल्ली के किडनी रोग विभाग के प्रमुख डॉ. दीपांकर भौमिक ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में किडनी की बीमारी का जल्द पता लगाने के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच कराने का सुझाव दिया।

गृह मंत्रालय ने केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार से सामान की खरीद पर जीएसटी पर 50 प्रतिशत की वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय एक अप्रैल से प्रभावी होगा। इस फैसले का उद्देश्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, केंद्रीय पुलिस संगठनों और राज्य पुलिस बलों के सेवारत तथा सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके परिवारों को लाभ पहुंचाना है। गौरतलब है कि केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार की स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी। वर्तमान में, 119 मास्टर भंडार और 1 हजार 700 से अधिक सहायक भंडार हैं। इसके माध्यम से बल कर्मियों को सस्ती दरों पर सामान उपलब्ध कराया जाता है।